

19

R. 266-11/2001

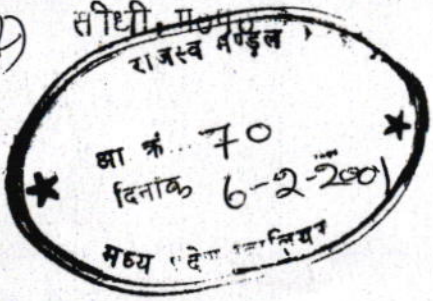


Stamped Rs. fifteen only 24/11/2001

resented by
Suri Shriram
Pandey Advocate
today on 24.11.2001
AS(B)

धर्मराज सिंह तनय अंशधारी सिंह उम्र 62 साल पेशा खेती साठ उपनी
तहसील गोपदबनास जिला सीधी, म०प० ----- आवेदक
बनाम,

म०प० राज्य शासन द्वारा राजस्व अधिकारी गोपदबनास जिला
सीधी, म०प० ----- अनाबेदक



निगरानी विच्छेद आदेश न्यायालय श्रीमान्
कलेक्टर महोदय जिला सीधी न पुकरण क्र०-
4/निगरानी/2000 आदेश दिनांक 23-10-2000
एवं पुकरण से संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों के
अधिष्ठाता, दुर्भाषिक कार्यवाहियों के संबंध में
अधीक्षणीय शक्ति के प्रयोग से अधीक्षणा र्थ ।
अन्तरगत धारारों 8 एवं 50 म०प० धू रा०सं०
1959

वि. नं. 70
दिनांक 6-2-2001

6-2-2001
मध्य प्रदेश न्याय

मान्यवर,

आवेदक का सविनय निगरानी आवेदन निम्नोक्त आधारों पर
पुस्तुत है :-----

--: निगरानी आवेदन के तथ्यात्मक बिन्दुएँ :-

1- यही आवेदक के स्वत्वाधिपत्ता की भूमि क्रमांक-486, 488 के चेक
के अन्तर्गत भूमि क्रमांक-487 रकबा 0-87 की स्थिति के संबंध में आवेदक
के पूर्ण भूमिस्वामी एवं उनके पश्चात उत्तराधिकार में प्राप्त कर स्वात्ता-
धिपत्ता में आने पर उनके चेक के अन्दर वादग्रस्त शासकीय भूमि होने या ग्रा
के रकबे के हिसाब से शासकीय भूमि को निस्तार पत्रक में लिखे जाने के
समय आवेदक के चेक के अन्दर भूमिशासन के आश्रय की वादग्रस्त भूमि होने की
जानकारी नहीं थी । भूमि पडताल के समय पटवारी हल्का ने भी उनके
चेक के अन्दर शासकीय भूमिशासन के लिये भूमि लिखी होने का तथा कभी
नहीं बतलाया था ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

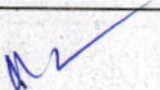
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक निग0 266-दो/2001

जिला-सीधी


स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
४ - ९ - 16	<p>आवेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित। अनावेदक की ओर से शासकीय अधिवक्ता उपस्थित।</p> <p>2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0क्र0 04/निग0/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 23.10.2000 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।</p> <p>3/ प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि विवादित भूमि, निरस्तार पत्रक में कब्रिस्तान श्मसान हेतु सुरक्षित है। जिस पर आवेदक अतिक्रामक की हैसियत से काबिज था, जिससे संहिता की धारा 248 के अधीन कार्यवाही की जाकर तहसीलदार गोपदबनास द्वारा प्रकरण क्रमांक 624/अ-68/94-95 में पारित आदेश दिनांक 31.08.95 द्वारा बेदखली का आदेश दिया गया है। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक की ओर से अवधि के बाद दिनांक 18.01.96 को अपील दायर की गई है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में भी</p>	





आवेदक की ओर से दायर की गई निगरानी भी समयावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई है । अवधि माफी के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्र में दिन प्रतिदिन हुये विलंब के कारणों को नहीं बतलेया गया है ।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि निस्तार पत्रक में श्मशान हेतु सुरक्षित है जिससे आवेदक को यह ज्ञात था कि इसका व्यवस्थापन नहीं हो सकता इसलिये उसने तहसीलदार के न्यायालय में पैरवी नहीं किया और अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी समय के भीतर कोई अपील नहीं दायर किया तथा अपर आयुक्त के न्यायालय में भी समय के भीतर निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार यह पाया गया कि आवेदक विधि के विपरीत अपना पक्ष समर्थन रखना चाहता है जो कि न्यायसंगत नहीं है । फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।


(के०सी० जैन)
सदस्य